



# राष्ट्रदूत

Rashtrdoot

Metro

Not Much Protects You  
And Your Personality!

Fame is earned, not public property. Being well-known  
does not mean the world gets to use you

The Times of Firuz  
Shah Tughlaq

A Stone  
To Protect  
And Cure

Scrappings from the ball were  
ingested as an antidote to  
poison and melancholy, as  
well as to prevent illness

## प.बंगाल में भाजपा ने अपनी पूर्ण विजय को “सील” किया

कलकत्ता नगर निगम को भी टीएमसी के नियंत्रण से मुक्त कराया

- अंजन रॉय -

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 5 जून। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत तब हुआ था, जब मित्र देशों की सेनाएं 1945-46 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुँचीं।

बंगाल में भाजपा की पूर्ण जीत पर उस समय मुहर लग गई जब उसने एक तरह से कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता कॉर्पोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उस ऐतिहासिक कक्ष में अपना पद छोड़ा, जहाँ कभी सुभाष चंद्र बोस मेयर की प्रतिष्ठित कुर्सी पर बैठे थे।

“देशबंधु” के नाम से प्रसिद्ध चित्रकार दास भी इसी मेयर की कुर्सी पर बैठे थे। एस्प्लेनेड स्थित कलकत्ता कॉर्पोरेशन का मुख्यालय, जिसे “बड़ा लालबाड़ी,” यानी “राष्ट्रसं बिल्डिंग” की तुलना में “छोटा लालबाड़ी” कहा जाता है, अब भाजपा के हाथों में जा रहा है।

हकीम द्वारा मेयर पद से इस्तीफा देने के साथ ही नगर निगम ने निगम बोर्ड को भंग करने की तैयारी शुरू कर दी है।

■ फिरहाद हाकिम ने मेयर के पद से इस्तीफा दे दिया है और कमिश्नर नगर निगम को भंग करने जा रहे हैं।

■ कलकत्ता के लोगों ने फिरहाद हाकिम के इस्तीफे पर खुशी जताई और उनकी कई शिकायतें कीं। बताया जाता है कि फिरहाद हाकिम ने एक बार कहा था कि हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि वे मुस्लिम परिवार में पैदा नहीं हुए हैं।

■ पूर्ण बंगाल विजय का दूसरा चरण नई दिल्ली में चल रहा है। टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलकर अलग गुट के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

■ चर्चा है कि सांसद शुभेन्द्र सेखर रॉय को इस गुट का नेता बनाया जा सकता है। जातव्य है कि सेखर के पिता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और प्र.मंत्री मोदी ने माल्दा में एक रैली में उनकी तारीफ भी की थी।

■ अगर तुणमूल सांसद अलग गुट बना लेते हैं तो इससे भविष्य में महत्वपूर्ण बिल पारित कराने में भाजपा को भारी मदद मिलेगी।

कलकत्ता कॉर्पोरेशन के आयुक्त अब निगम बोर्ड को भंग कर प्रशासन अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं।

कट्टर कलकत्ता प्रेमी अब सामने आकर मेयर के कार्यकाल के दौरान उनके आचरण की तीखी आलोचना कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अपने प्रभावशाली दौर में फिरहाद हकीम ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन की परंपराओं का सम्मान नहीं किया।

उनके विरोधियों का आरोप है कि पद पर रहते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की

थी कि बहुसंख्यक हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में नहीं हुआ। इस टिप्पणी से बहुसंख्यक समुदाय में व्यापक नाराजगी पैदा हुई थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## क्या संवर्धित यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने की शर्त छोड़ दी है ट्रंप ने?

“पल में तोला पल में माशा” कहावत को चरितार्थ करने वाले ट्रंप ने यह कहकर सभी को हैरान कर दिया कि संवर्धित यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने का मुद्दा “दफन” हो चुका है

- डॉ. सतीश मिश्रा -

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 5 जून। एक और हैरान करने वाले बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन को ईरान के साथ ऐसे शांति समझौते की जरूरत नहीं है, जिसमें इस्लामी गणराज्य के संवर्धित यूरेनियम (एनरिचड यूरेनियम) को देश से बाहर ले जाने की शर्त हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है, तो ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामनेई से मिलना उनके लिए

■ अपने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना द्वारा संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर जाने का विचार उन्हें पसंद नहीं है। ट्रंप की इस टिप्पणी ने सभी को हतप्रभ कर दिया, क्योंकि पूर्व में कई बार ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान ने यूरेनियम नहीं ले जाने दिया तो वे उसका नामोनिशान मिटा देंगे।

■ ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर दोनों देशों के बीच डील हो गई तो वे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा से मिलना चाहेंगे और यह उनके लिए सम्मान की बात होगी।

“सम्मान की बात” होगी। अपने हमेशा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## हाई कोर्ट ने जल जीवन मिशन की सुनवाई एसीबी-2 को भेजी

जयपुर, 5 जून। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अब एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 सुनवाई करेगी। एसीबी कोर्ट-1 के पीठासीन अधिकारी की ओर से इस संबंध में हाईकोर्ट को पत्र लिखकर केस ट्रांसफर करने की गुहार की गई थी। इसके

■ एसीबी कोर्ट-1 के पीठासीन अधिकारी ने हाई कोर्ट को पत्र लिखकर केस ट्रांसफर करने की प्रार्थना की थी।

बाद, हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से मामले को लेकर एसीबी कोर्ट में लिखित मामलों को क्रम-2 कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया है, जहाँ अदालत मामले की सुनवाई 8 जून से करेगी। वहीं तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य पीएचईडी सचिव और रिटायर आईएएस सुबोध अग्रवाल की जमानत अर्जी पर भी अब 8 जून को सुनवाई होगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## सरकार बनाने के साथ ही मुश्किल शुरु हुई शिवकुमार की

शपथ लेने के दो दिन बाद ही एक वरिष्ठ मंत्री ने इस्तीफा दिया व कई अन्य ने विभाग के प्रति असंतोष जताया

- जाल खंबाटा -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 5 जून। कर्नाटक के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो कई अन्य मंत्री बेहतर विभाग की मांग कर रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता उपेक्षा से नाराज हैं, मुस्लिम नेताओं ने मंत्रिमंडल में बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग उठाई है, और महिलाओं को प्रतिनिधित्व न मिलने पर भी आलोचना हो रही है। तीन दिन पुरानी डीके शिवकुमार सरकार आंतरिक राजनीतिक संकट में घिर गई है।

अब तक चार मंत्रियों ने हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। पहला झटका शुक्रवार सुबह तब लगा, जब मंत्री रामलिंग रेड्डी ने यह कहते हुए इस्तीफा भेज दिया कि उन्हें आवंटित विभाग से वे असंतुष्ट हैं। इसके तुरंत बाद नई सरकार के दूसरे मंत्री के.एच.

■ वरिष्ठ मंत्री रामलिंग रेड्डी को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है, उन्होंने कहा कि वरिष्ठतम नेता होने के नाते उन्हें बेहतर विभाग मिलना चाहिए। रेड्डी ने कहा, उन्हें बंगलुरु विकास विभाग देने का वादा किया गया था।

■ एक अन्य मंत्री, के.ए. मुनिपप्पा, जो सात बार कोलार सीट से सांसद रहे हैं और वर्तमान में देवन हल्ली से विधायक हैं, ने विभाग के प्रति नाराजगी जताई। एक अन्य विधायक के.जे. जॉर्ज अपने विभाग में किए जा रहे तबादलों से नाराज हैं।

■ वहीं सतीश जारकीहोली को हालांकि उनका सार्वजनिक निर्माण विभाग पुनः मिला गया, पर, उनकी इच्छा प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी है।

मुनियप्पा ने भी अपने मंत्रालय को लेकर असंतोष व्यक्त किया। इसके बाद असंतोष का स्वर और तेज हो गया। मंत्री

के.जे. जॉर्ज अपने विभाग में कथित “हस्तक्षेप” से नाराज बताए जा रहे हैं, जबकि सतीश जारकीहोली ने स्पष्ट कर

दिया है कि उनकी महत्वाकांक्षा केवल मंत्री पद तक सीमित नहीं थी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पाने वाले मुनियप्पा ने कहा कि पार्टी के “सबसे वरिष्ठ” नेताओं में से एक होने के नाते, वे इससे बेहतर विभाग के हकदार थे।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपनी अपेक्षाओं के बारे में राहुल गांधी सहित, पार्टी नेतृत्व को पहले ही अवगत करा दिया था।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे दिए गए विभाग से नाराज हैं, तो मुनियप्पा ने कहा कि उन्हें ऐसा “महत्वपूर्ण विभाग” दिया जाना चाहिए जहाँ वे जगता के लिए बेहतर ढंग से काम कर सकें।

के.एच. मुनियप्पा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कोलार लोकसभा सीट से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## चर्चित शिक्षक खान सर के खिलाफ

एफआईआर दर्ज

पटना, 05 जून। राजधानी पटना में चर्चित शिक्षक और कोचिंग संचालक खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कदमकुआं थाना में उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और अस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) से संबंधित

■ कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश तथा आर्म्स एक्ट में भी धाराओं में मामला दर्ज हुआ।

धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा दर्ज मामले के बाद पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है और जब एजेंसियां मामले की विस्तृत पड़ताल में जुट गई हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मामला खान सर के सुरक्षा गार्डों के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## सरकारी बाँण्ड में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को वित्त मंत्रालय ने दी भारी टैक्स छूट

ईरान युद्ध, महंगा तेल, रुपये की गिरती कीमत और तीन दिन में विदेशी निवेशकों द्वारा 34,000 करोड़ रुपये निकाला जाना है इस फैसले की बुनियाद

-कार्यालय संवाददाता-  
नई दिल्ली, 5 जून। वैश्विक पूंजी को आकर्षित करते हुए, सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी निवेश संस्थानों (एफपीआई) द्वारा किए गए निवेशों पर लागू कर व्यवस्था को युक्ति संगत बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत, ऐसे निवेशों को ब्याज या पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट दी जाएगी। इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान व्यवस्था कई तुलनीय देशों के अनुरूप हो जाएगी।

यह छूट 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इसका अर्थ है कि जी-सेक (गवर्नमेंट सैक्टर बाँण्ड) में निवेश

से जुड़े मामलों में एफपीआई को 01 अप्रैल 2026 या उसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी तरह के ब्याज या पूंजीगत लाभ पर यह छूट लागू होगी।

सरकार ने दीर्घकालिक एवं स्थिर पूंजी आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ कर हटाने का फैसला किया है, क्योंकि इन माध्यमों की अवधि लंबी होती है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब विदेशी निवेशकों ने इस वर्ष अब तक स्थानीय शेयर बाजार से 2.6 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं, जो 2025 में निकाले गए 1.66 लाख करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। इसकी वजह वैश्विक अनिश्चितता रही है। केवल जून के पहले

■ उल्लेखनीय है इस वर्ष अब तक स्थानीय शेयर बाजार से 2.6 लाख करोड़ रुपये की निकासी हुई है, जो 2025 में निकाले गए 1.66 लाख करोड़ रुपये से कहीं अधिक है।

■ वहीं ईरान युद्ध और उससे जुड़े आर्थिक संकटों के कारण रुपया 20 मई, 2026 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.86 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था।

तीनदिन में ही विदेशी निवेशकों ने शेयरों से करीब 34,000 करोड़ रुपये निकाले, जिससे रुपये पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।

सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती के अनुसार इन प्रयासों का उद्देश्य भारतीय इक्विटी बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशकों का दायरा बढ़ाना है, साथ ही दुनिया की सबसे तेजी

से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक में निवेश करने के इच्छुक वैश्विक निवेशकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इससे टिकाऊ और निरंतर विदेशी पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित होगा, जो दीर्घकालिक निवेशकों जैसे पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और संप्रभु धन कोष (एसडब्ल्यूएफ) के रूप में स्थिर और

व्यवस्थित तरीके से आएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार इन उपायों से एक सुचारू उपज वक्र के विकास में मदद मिलेगी और पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और संप्रभु धन कोष जैसे दीर्घकालिक निवेशकों सहित दीर्घकालिक, विदेशी पूंजी का स्थिर व्यवस्थित प्रवाह आकर्षित होगा। इससे देश में विदेशी मुद्रा प्रवाह को भी बढ़ावा

मिलने की उम्मीद है।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसमें 15,30 और 40 वर्षों की अवधि के सरकारी प्रतिभूतियों के नए निर्गमों के साथ-साथ एफएआर-पात्र प्रतिभूतियों की अवधि के संप्रभु हरित बाँड (एसजीआरबी) को भी शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सामान्य मार्ग के अंतर्गत एफपीआई निवेशों के संबंध में, विदेशी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)